

प्रेषक,

जो०पी०जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

राजस्व अनुभाग-२

देहरादून: दिनांक: १३ अगस्त, 2015

विषय:- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (R SETI), उत्तरकाशी की स्थापना हेतु कुल ०.३४० है० भूमि ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-४१५८ / आठ-९(२००९-१०) दि०-३०.०६.२०१५ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद उत्तरकाशी की तहसील भटवाड़ी, पट्टी बाड़ाहाट के ग्राम हीना के खोखा० सं०-०७ के खसरा सं०-२२१२ मध्ये ०.०२३, २२१४ रक्बा ०.१०३, २२१५ रक्बा ०.०७०, २२१७ रक्बा ०.०५६, २२१९ रक्बा ०.०३८ तथा २२२१ रक्बा ०.०५० इस प्रकार कुल ०.३४० है०, श्रेणी-१क उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० के नाम दर्ज भूमि को वित्त अनुभाग-३ के शासनादेश सं०-२६० / वित्त अनुभाग-३ / २००२ दि०-१५.०२.२००२ के प्राविधानों के अधीन तथा ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की विभागीय सहमति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- १— भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- २— जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- ३— हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- ४— यदि भूमि की आवश्यकता न हो या ३ वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- ५— जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- ६— जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- ७— प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- ८— प्रश्नगत जेड०४० भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-१३२ एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

- 9— इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या-3109/201
श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील सं0-436,
2011/SLP(C) NO. 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य
में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दि0—जनवरी, 2011 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय
के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10— आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 09 में से किसी भी
शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित है
जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

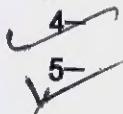
कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश व
परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथ
समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

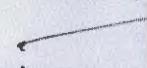

(जो0पी0 जोशी)
अपर सचिव।

पृ0प०संख्या— / समदिनांकित / 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— सचिव, ग्राम्य विकास / ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3— आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
 4— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(आलोक कुमार सिंह)
अनुसचिव।